शहरी भारत

खण्ड 28 जनवरी-दिसम्बर 2008, संख्या 1 व 2

विषय-सूची

संपादकीय

लेख

विशाल भारतीय शहरों में निरंतर जल आपूर्ति हेतु पानी के बड़े जलाशयों (रिज़रवॉयर्स) की भूमिका
सच्चिदानंद मुखर्जी, जंखाना शाह तथा डा. एम दिनेश कुमार

विशेष आर्थिक क्षेत्र – स्थानीय सरकार की अनदेखी (बाइपासिंग) ?
डा. शिप्रा मैत्रा

आंध्रा प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय परफारमेंस – एक मूल्यांकन
डा. एस. सुधाकर

मेगासिटी का उदगमन: हैदराबाद के उप-शहरी क्षेत्रों के दलितों पर प्रभाव
बी. सुरेश रेड्डी

लेखाकरण की कमियों का लेखा: छोटे नगरों व शहरों की म्युनिसिपल निकायों में वित्तीय रिपोर्टिंग की चिरकालीन समस्या
डा. संजुक्ता रे

मूल शहरी सेवाओं के मानदंड व स्तर – एक समीक्षा
डा. मुकेश पी.माथुर तथा डा. राजेश चन्द्रा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना व प्रबंधन
डा. बरून कुमार

शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की उत्पत्ति करना – गुवाहाटी शहर का एक केस अध्ययन
उपासना चक्रवर्ती तथा डा. निस्सार ए. बारूआ

अहमदाबाद में अंतर्विस्ट सोसायटी की कूट रचना
डा. शैलजा मेनन

अरूणाचल प्रदेश में शहरीकरण – परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएँ
मनीष शर्मा

कार्यशाला की कार्यवाही

" विश्व विकास रिपोर्ट 2009 की कार्यशाला की कार्यवाही : आर्थिक भूगोल को पुनर्गठित करना " पर शहरी विकास मंत्रालय और रा.न.का.सं. द्वारा 12 मार्च 2009 को आयोजित कार्यशाला की गई।
ऊषा पी. रघुपती व दिबेन्दु सामन्ता

पुस्तक समीक्षा

शहरी विकास रिपोर्ट, 2009, *आर्थिक भूगोल का पुनर्गठन*,
विश्व बैंक, वाशिंगटन, 2009
डा. बसुधा चट्टोपाध्याय

पिछले खण्ड XXVII, संख्या 1, जनवरी-जून 2007 की विषय सूची

सारांश

विशाल भारतीय शहरों में निरन्तर जल-आपूर्ति हेतु पानी के बड़े जलाशयों की भूमिका

सच्चिदानंद मुखर्जी, जंखाना शाह और एम.दिनेश कुमार

शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि और तीव्र औद्योगिकरण के कारण भारत में शहरी जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में शहरी नियोजकों के लिए इस मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। प्रसंगवश, बहुत से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तथा उनमें से अधिकतर शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, जिनमें प्राकृतिक रूप से ही अपर्याप्त जल है। परिणामस्वरूप, भूमिगत जल सहित स्थानीय जल संसाधनों से अधिकतर शहरी क्षेत्रों में अधिक व केन्द्रिय मांग हेतु जल आपूर्ति कम पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में, इन बड़े शहरों को दूर बनी हुई पानी के बड़े जलाशयों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में शहरी जनसंख्या में वृद्धि का ढांचा व संरचना बताते हुए, यह लेख यह तर्क प्रस्तुत करता है कि पानी के बड़े जलाशयों से जल आपूर्ति की अनुपस्थिति में शहरीकरण संकट में आ जाएगा। 302 शहरी केन्द्रों का विश्लेषण दर्शाता है कि अधिक जनसंख्या वाले शहरों की भूमिगत जल स्रोतों पर निर्भरता कहीं अधिक है। यह भी कि, शहरी जल आपूर्ति का जितना भाग अधिक होगा, प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति का स्तर उतना ही अधिक होगा। 190 प्रथम श्रेणी के शहरों तथा 240 द्वितीय श्रेणी के शहरों का मल्टीपल रिगटेशन विश्लेषण इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। बड़े शहरों में, जनसंख्या में प्रत्येक इकाई की बढ़ोतरी के साथ, प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति में 1.12 इकाई में वृद्धि होती है। भविष्य की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक स्थितियां तथा पानी की मांग को देखते हुए बड़े जलाशयों की शहरी जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र – स्थानीय सरकार की अनदेखी ?

शिप्रा मैत्री

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा विकास पर इसके प्रभाव ने विश्व के अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ नियोजकों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि ये निर्यात को प्रोत्साहन के साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने, बेरोजगारी कम करने के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, आय उत्पन्न करने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायता करने को संभव बनाता है। ये वृहत-आर्थिक लाभ कुछ प्रमुख सूक्ष्म-आर्थिक मुद्दों से जुडे हुए हैं जिससे कि कुछ गंभीर मामले उत्पन्न हुए हैं। भूमि, दीर्घकालिक विकास में एक गंभीर अवरोध है। कृषि-योग्य भूमि का अन्य प्रयोग में भूमि-रूपांतरण से जीविका में परिवर्तन होता है जो कि एक सरल प्रक्रिया नहीं है। औद्योगिकरण से विस्थापित कामगारों के लिए नियमित रोजगार की व्यवस्था करना एक दुर्जेय चुनौती है। एस.ई.जेड. से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा यह है कि यह स्थानीय स्थितियों को नजरअंदाज करता है। एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 स्थानीय निकायों को संबंद्धित किए बिना केन्द्र व राज्य सरकारों की भूमिका को दर्शाता है। एस.ई.जेड. के अंतर्गत आने वाली आर्थिक इकाईयाँ निश्चित अवधि के लिए कर-छूट और अन्य रियायतों का लाभ उठाएंगें। उन्हें स्थानीय निकायों से किसी प्रकार के लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। वे सामान्य पर्यावरणीय नियंत्रणों से मुक्त होंगे अतः कोई स्थानीय प्रदूषण कर नहीं होगा। स्थानीय निकाय इस नए आर्थिक ढांचे से न तो राजस्व अर्जित कर रहे हैं और न ही उनकी एस.ई.जेड. प्रबंध में कोई अधिकार है। संविधान ने यू.एल.बी. के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार किया है। एस.ई.जेड. के रूप में नई अर्थव्यवस्था का उदगमन इन भूमिकाओं को चुनौती दे रहा है। यह लेख इन विषयों पर ध्यान दिलाने का प्रयास करता है तथा नई अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुसार दीर्घकालिक विकास के केन्द्र में स्थानीय निकायों को रखने का तर्क देता है।

आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व संबंधी कार्य प्रदर्शन – एक मूल्यांकन

प्रो. एस. सुधाकर

शहरीकरण, विकास प्रक्रिया का एक परिणाम है। जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्रों में आय वृद्धि की तुलना में बुनियादी ढांचे तथा मूल सेवाओं में वृद्धि पिछड़ रही है। इस संदर्भ में, शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को आवश्यक शहरी सेवाएं उपलब्ध कराने में भूमिका अदा करनी होगी। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए यू.एल.बी. की क्षमता उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन का लक्ष्य वर्ष 2006-07 के लिए चुनिंदा वित्तीय कार्य-निष्पादन सूचकों पर आधारित मानक और आदर्श दोनों मार्गों का प्रयोग करते हुए आंध्र-प्रदेश के 14 नगर-निगमों (म्युनिसिपल कॉरपोरेशन-एम.सी.) के वित्त या राजस्व संबंधी कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना है। यह 14 एम.सी. के अन्तर्गत जल आपूर्ति, सड़क, बिजली और निकासी पर होने वाले व्यय का अनुमान, जकारिया समिति (1963) के मानदण्डों, जो कि वर्ष 2006-07 की थोक मूल्य सूची के आधार पर है, लगाता है। मानक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी 14 नगर निगमों के पास वर्ष 2006-07 के बजट में से आय और वित्तीय दोनों राशियां अधिक हो गई। मानदंड सम्बन्धी दृष्टिकोण के अंतर्गत, जब आय और वित्तीय राशियों में चार सेवाओं पर किए गए कम व्यय को जोड़ा गया तो मानकीय वित्तीय और आय राशियां 2601.47 करोड़ रू. तथा 27.29 करोड़ रूपये क्रमश: का घाटा दर्शाती हैं। इस घाटे के परिणामस्वरूप, नगर निगमों को अपने आय के वित्त- पोषण के लिए 27-29 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय-प्राप्तियां बढ़ानी पड़ती है।

मेगासिटी का उदगमन : हैदराबाद के उप-शहरी क्षेत्रों के दलितों पर प्रभाव

बी. सुरेश रेड्डी

भूमि प्रयोग के परिवर्तन के कारण मेगासिटी हैदराबाद के बाह्य शहरी क्षेत्र असाधारण परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उसी प्रकार वहाँ के दलितों के जीवन में परिवर्तन हो रहा हैं। हैदराबाद के आस-पास के क्षेत्रों का अध्ययन दलितों के जारी विकास पर प्रभाव को उजागर करता है। यह लेख इस बात पर चर्चा करता है कि किस प्रकार ये अधिकांश सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि ये परिवर्तनों को समझ पाने में असमर्थ हैं, विशेषकर रियल-एस्टेट मार्किट में आ रही तेजी को। उनको इस तेजी की शायद ही कोई जानकारी हो तथा इसीलिए वे अपनी जमीनें बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं जिससे वे सदा ही गरीब बने रहेंगे। यह लेख बताता है कि कुछ मामलों में दलितों को अपनी जमीने बेचने के लिए किस प्रकार रियलएस्टेट दलालों के द्वारा गुमराह और धमकाया जाता है। विकास से संबंधित गतिविधियों के कारण विस्थापित लोगों के पास पुनर्वास क्षेत्रों में मूल सुविधाओं की कमी है। यह लेख दलितों की जमीनों की सुरक्षा के लिए तर्क देता है। इस लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक वकालत सेल होना चाहिए जिससे भूमि के प्रयोग में परिवर्तन होने पर दलित मार्ग दर्शन के लिए जा सके तथा भू-मफिया से कानूनी संरक्षण पा सकें।

लेखाकरण और वित्तीय: रिपोर्ट देना : भारत के छोटे और मध्यम नगरों के नगर-निकायों की चिरकालीन समस्याएं

डा. संजुक्ता रे

भारत के शहरी क्षेत्रों में अभूतपूर्व बढ़ती आबादी के दबाव से नीति-निर्माण की योजना के केन्द्रीय चरण में कुशल शहरी प्रशासन का मुद्दा उत्पन्न हुआ है। शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार आरम्भ हो रहे हैं। दुर्भाग्य से, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में अभूतपूर्व लेखांकन सुधार छिटपुट, अपर्याप्त है और उसमें भारत के छोटे शहरों की विशेष जरूरतों की अनदेखी की है। उन्होंने लेखा-प्रणाली को "नकदी आधारित एकल प्रविष्टि" (कैश बेस्ड सिंगल एंट्री) से "प्रोदभवन आधारित दोहरी प्रविष्टि " (एक्रुअल बेस्ड डबल एंट्री) में रूपांतरित करने पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित किया तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में अपेक्षित आवश्यक सुधारों पर बहुत कम ध्यान दिया।

छोटे और मध्यम आकार के नगरों के विशेष लाभ और विशिष्ट लक्षण होते हैं जो कि उनको आर्थिक विकास के भावी इंजिन के रूप में क्षमता प्रदान करते हैं। वर्तमान में, वे अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, विशेषकर वित्तीय लेखा करण और वित्तीय रिपोर्टिंग में। उन्होंने काफी समय से हर ओर से उपेक्षा का सामना किया हैं। वे वित्तीय और संस्थागत बाधाओं के कारण निकट भविष्य में दोहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली(डबल एंट्री एकाउंटिंग सिस्टम) में परिवर्तित होने की स्थिति में नहीं है। तब तक वित्तीय रिपोर्टिंग में कुछ मामूली सुधार से अधिक आवश्यक बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सकती है।

मूल-शहरी सेवाओं के मानदंड(नॉर्मस) और स्तर (स्टैन्र्डडस) – एक स्थितिगत समीक्षा

डा. मुकेश पी. माथुर और डा. राजेश चन्द्रा

विभिन्न आकारों, आयामों के शहरी क्षेत्रों में सेवाओं तथा आर्थिक गतिविधियों का क्या स्तर प्रदान किया जाना चाहिए तथा क्या स्तर बनाए रखा जाना चाहिए, इस प्रश्न पर विभिन्न मंचों पर बहस की गई। ऐसा देखा गया है कि मूल शहरी सेवाओं के मानदंडों और स्तरों को निर्धारित करना एक जटिल और महत्वपूर्ण कार्य है।

मानदण्ड और स्तर अनेक घटकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि स्थानीय निकायों तथा प्रयोक्ताओं की वित्तीय क्षमता, संबंधित सैटलमैंट की स्थलाकृति और भूविज्ञान, बुनियादी ढांचे के विकास का पूर्व-इतिहास, जनसंख्या का आकार तथा अन्य आर्थिक व गैर-आर्थिक घटक। अनेक एजेन्सियों तथा विशेषज्ञ समूह समितियों ने भारत में बुनियादी ढांचे और सेवाओं हेतु भौतिक के साथ-साथ वित्तीय स्तर के अनेक विकल्प उपलब्ध कराए है। इस लेख में, मूल सेवाओं अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा संग्रहण और निपटान, प्राथमिक शिक्षा तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मानदण्डों और स्तरों की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। सुझाए गए मानदण्ड अभ्यासरत नगर योजना-संगठनों तथा स्थानीय निकायों द्वारा तत्काल संदर्भ हेतु उपयोगी हो सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और प्रबंधन

डा. बरून कुमार

यह लेख विकासशील देशों के मेगा-शहरों में विभिन्न शहरी खतरों पर चर्चा करता है तथा एन.सी.आर. योजना हेतु नई-जानकारी प्रदान करता है। विकासशील देशों में मेगा शहर विभिन्न आर्थिक, पर्यावरणीय, प्रबंधन तथा सामाजिक खतरों का सामना कर रहे हैं। आगे, शहरी अर्थव्यवस्था कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण मूल उद्योगों के अपेक्षित स्तर को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। आरम्भ में, एन.सी.आर. की योजना और प्रबन्धन के लिए विभिन्न उभरते हुए मुद्दों को उठाया गया है। यह क्षेत्रीय असमानताओं, भूमि अधिगृहण, बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट विकास, उद्योगों का चुनाव, संसाधनों का प्रयोग, प्रौद्योगिकी, मानव शक्ति, समानता और न्याय तथा अंत में उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित है। एन.सी.आर. के सतत विकास के लिए व्यापक दृष्टि और उद्देश्यों के उल्लेख का भी प्रयास किया गया। इस लेख के अंत में कुछ सुझाव दिए गए जो प्रथम, समान्यतः दिल्ली तथा विशेषकर एन.सी.आर. में शहरी आधार को मजबूत करने, द्वितीय गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा तथा गाजियाबाद के अलावा सी.एन.सी.आर. नगरों की बुनियादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के विषय में, तृतीय अन्य शहरों में श्रेष्ठ कार्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि हस्तांतरण के आधार पर एस.ई.जेड. के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों के विषय में, चतुर्थ रियल एस्टेट उद्योग को बुनियादी ढांचे और क्षेत्र के भूनिर्माण की लागत वहन करने से संबंधित है।

विकासशील देशों में मेगा-शहरों का प्रबंधन शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण, बुनियादी ढांचे की मांग व आपूर्ति में बढ़ते हुए अंतर के कारण, वैश्विकरण और ट्रांस नेशनल प्रैक्टिसस (टी.एम.पी.) आदि के कारण शहरी गरीबों की उपेक्षा के कारण बड़ी चुनौती बन गया है। ये समस्याएं बेकार शहरी प्रबंधन और शासन के कारण बिगड़ गई है। नव-आर्थिक विकास को उत्पन्न करके उसे बढ़ाने की आवश्यकता है जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करें अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनोमिक जोन-SEZ) तथा निर्यात प्रोत्साहन जोन को बनाना। निर्माण या सेवाओं से संबंधित मूल गतिविधियां किसी भी शहर की जीवन रेखा है। शहरी आर्थिक आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचा निर्मित करने और शासन में सुधार लाने की आवश्यकता है। परंतु यह विकास गतिशीलता तभी बनाई रखी जाएगी जब हम पर्यावरणीय व सामाजिक खतरों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करते हैं तथा एन.सी.आर. की समावेशी व पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं।

शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार-सृजन:
गुवाहाटी शहर का केस – अध्ययन

उपासना चक्रवर्ती
डा. निस्सार ए.बरूआ

प्रकृति में अत्यंत विषम शहरी केंद्रित अनौपचारिक क्षेत्र असंगठित, अनियमित, अपंजीकृत तथा श्रम-प्रधान गतिविधियों का एक चित्र दर्शाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति से देश के बदलते समाजिक-आर्थिक ढांचे के कारण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया है। गुवाहाटी में तेजी से शहरीकरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के साथ असम इस प्रवृति के लिए कोई अपवाद नहीं है। गुवाहाटी और असम के लिए रोजगार सृजन के इंजिन के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता जहां चिरकालीन बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर आर्थिक और सामाजिक-राजनैतिक संकट उत्पन्न किए है। इस अध्ययन का उद्देश्य गुवाहाटी शहर में अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए एक संचालन-पद्धति को ढूंढ निकालना है। इस अध्ययन का उद्देश्य दस वर्षों के अध्ययन काल में अनौपचारिक क्षेत्र में सृजित रोजगार का अनुमान लगाना है। इस अनुमान के आधार पर, लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल सृजित रोजगार में 90 प्रतिशत के योगदान से अनौपचारिक क्षेत्र ने गुवाहाटी अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र की महत्ता को स्वीकार करते हुए यह लेख मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है।

अहमदाबाद में एक समग्र समाज को गढ़ने की कोशिश

डा. शैलजा मेनन

अहमदाबाद अपनी सांप्रदायिक हिंसा के लिए देश के मस्तिष्क पर अंकित है। चाहे वह पंतगबाजी, गणेश उत्सव, रथयात्रा, मुहर्रम का त्यौहार हो, उसमें अनिवार्य रूप से टकराव हो जाता है। शहरवासी शहर के सांप्रदायिक संघर्ष (स्ट्राइफ) की नकारात्मक रिपोर्ट से संतृप्त हो जाता है जिसमें मृत अथवा घायलों के आंकड़ों की सुर्खियां होती है और शेष राष्ट्रीय दैनिक सामाचार पत्रों के भीतर पन्नों में दफन हो जाता है। हालांकि कोई शहर जो अहमदाबाद की तरह भव्य व्यापार परंपरा का दावा करता है वह अपने व्यापार का पटरी से उतरना नहीं झेल सकता है।

कोई व्यक्ति अहमदाबाद में एक नागरिक समाज के टूटने की व्याख्या कैसे करता है? इस संघर्ष को एक शहर किस प्रणाली द्वारा नियंत्रित करता है? क्या अंतर-जातीय, आर्थिक-प्रतिद्वंद्विता, विपक्षी-पार्टी की राजनीति अथवा अलग पड़ोसी इलाकों (नेबरहुड्स) की हिंसा की व्याख्या करना संभव है? कौन से कारक हिंसा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से शांति की स्थिति को पृथक करते है? यह लेख अहमदाबाद के नागरिक जीवन के ढांचे को उजागर करता है जिसने राजनीतिक कार्यनीतियों एवं उनके परिणामों पर प्रभाव डाला है। नागरिक जीवन में व्यवधान ने अहमदाबाद को हिंसा के अंतहीन पेचीदा संघर्ष में धकेल दिया। स्थायी शांति की शुरूआत करने के लिए सैहार्द और सहयोग की वैकल्पिक बातचीत आवश्यक है। राज्य और नागरिक समाज के बीच कोई विरोधी रिश्ता नहीं हो सकता है। जब स्थानीय शहरी निकायों द्वारा मूलभूत-सुविधाओं का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला जाता है तो राज्य-नागरिक समाज के तालमेल से स्थानीय हिंसा रोकने की लाभदायक संभावनाएं उत्पन्न होती है। एक सुदृढ़ समाज के निर्माण से राज्य सरलता से दंगों को रोक सकते हैं। ऐसे निर्माण के बिना, राज्य के सक्षम अधिकारी हिंसा को रोकने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं।

अरूणाचल प्रदेश में शहरीकरण – परिप्रेक्ष्य, एवं संभावनाएं

मनीष शर्मा

सारांश

अरूणाचल प्रदेश के उत्तर-पूर्वीय भारतीय राज्य विभिन्न भाषा और जाति की पृष्ठभूमि वाली जनजाति की बड़ी संख्या का धर है। ये जनजातियां अपनी व्यवस्था के दायरे में न्यायोचित एवं सतत ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की गोद में मैत्री भावपूर्ण ढंग से रह रहे थे। बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पादन, विनिमय तथा विकास के स्तर में बढ़ती हुई जटिलता के कारण जनसंख्या का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं। विभिन्न प्रशासनिक व अन्य संगठनों के विस्तार के कारण, शहरीकरण की गति में बढ़ोतरी हुई, विशेषकर 1971 के बाद राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात् । 1971 की जनगणना के पहले की शहरी जनसंख्या का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जब यह केवल 3.70% थी, वर्ष 2001 में यह बढ़कर 21.34% हो गई। हालांकि जनजाति प्रधान पहाड़ी राज्य होने के कारण राज्य में शहरीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक न होकर उत्प्रेरित है।

इस लेख में, शहरीकरण की परिस्थिति व प्रक्रिया, इसके सामाजिक-आर्थिक सहसम्बद्ध तथा इसके परिणामों की जांच करने के लिए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों की सहायता से राज्य की परिस्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया है।